

# राजस्थान पुलिस ने जारी की 25 वॉन्टेड बदमाशों की लिस्ट, लॉरेंस के गुर्गे का नाम भी शामिल

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

राजस्थान पुलिस ने सूबे में आपराधिक वारदातों को कम करने के लिए 25 मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों की एक नई लिस्ट जारी की है। इसमें गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कुछ बदमाशों के नाम भी शामिल हैं। अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन ने गुरुवार को यह लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में गंभीर अपराधों में शामिल 12 नए अपराधियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें से कई बदमाशों पर तो लाखों रुपये का नकद इनाम है। इसके साथ ही एडीजी ने सूबे के तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लिस्ट में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करने को कहा है। एडीजी ने जयपुर और जोधपुर के पुलिस आयुक्तों, सभी रेंज आईजी, जिला एसपी, डीसीपी, जीआरपी अधिकारियों और एटीएस/एसओजी इकाइयों को इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने कहा कि ये 25 बदमाश समाज के लिए एक गंभीर खतरा हैं। इन्हें गिरफ्तार



करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में सूबे की सभी पुलिस यूनिट इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोऑर्डिनेश के तहत काम करेंगी। एडीजी ने कहा कि हम जनता से भी गुजारिश करते हैं कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के साथ कोई भी जानकारी साझा करें। इस लिस्ट में हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम उल्लंघन, एनडीपीएस अधिनियम और चोरी के मामलों में वॉन्टेड बदमाशों को

शामिल किया गया है। इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का बदमाश रोहित गोदारा का नाम भी शामिल है। रोहित गोदारा हत्या और डकैती के 20 मामलों में वॉन्टेड है। राजस्थान पुलिस की ओर से रोहित गोदारा पर 1 लाख रुपये और एनआईए की ओर से 5 लाख रुपये का इनाम है। इस लिस्ट में महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल का नाम भी शामिल है। वह हत्या के प्रयास और चोरी सहित 25 मामलों में वॉन्टेड है। उस पर एनआईए की ओर से 5

लाख रुपये और राज्य पुलिस की ओर से 2 लाख रुपये का इनाम है। लिस्ट में वीरेंद्र सिंह चारण, सतविंदर उर्फ गोल्डी बराड़, अनमोल उर्फ भानु, श्याम सुंदर उर्फ सांवरिया, सुनील कालू मीणा और अनिल पांड्या के नाम भी शामिल हैं। इन पर 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का इनाम है। लिस्ट में महेश हरिजन, अमरजीत विश्नोई, सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल और अजय सिंह उर्फ अज्जू बाना का नाम भी शामिल है।

## चित्तौड़गढ़ में टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के अश्लील वीडियो बनाए: बच्चों से आपस में धिनाई हरकत करवाता था

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

चित्तौड़गढ़ में 59 साल के सरकारी टीचर ने स्कूल में अपने ही स्टूडेंट्स का अश्लील वीडियो बनाए। बच्चों से आपस में अश्लील हरकतें करवाता था। 2 साल से टीचर यह धिनाई हरकत कर रहा था। वह बच्चों को फेल करने की धमकी देता था। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीचर को निलंबित कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- वीडियो देखकर लगता है यह टीचर नहीं, राक्षस है। टीचर की धिनाई हरकतें कैसे हुई उजागर... मामला बेगू इलाके का है। एक स्टूडेंट ने घरवालों को स्कूल में आगे की क्लास में एडमिशन कराने से मना कर दिया। बच्चा स्कूल से टीसी कटाने की जिद करने लगा। बच्चे को विश्वास में लेकर घरवालों ने कारण पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। घरवालों को मामले का पता चलते ही उन्होंने गांव के लोगों को शिक्षक की हरकत के बारे में बताया।



इसके बाद गांव वाले आज सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। लोग स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। नायब तहसीलदार विष्णु यादव, थानाधिकारी शिवलाल मीणा मौके पर पहुंचे और गांव वालों से समझाइश की। दो साल से चल रहा था टीचर का गंदा खेल... एक बच्चे के परिजन ने बताया- टीचर 2 साल से स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। जिससे लड़के और लड़कियां परेशान थे। टीचर खुद बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता और बच्चों से आपस में

अश्लील हरकतें करने को कहता। इनके वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रखता। फिर बच्चों को धमकियां देता कि किसी को बताया तो फेल कर दूंगा। अश्लील हरकतों से पीड़ित बच्चे 12 से 18 साल तक के हैं। गांव के व्यक्ति ने बताया- आरोपी ग्रेड थर्ड टीचर है। वह पिछले 7 साल से इस स्कूल में कार्यरत है। वह पहली से 5वीं कक्षा को अंग्रेजी और गणित पढ़ाता है। जानकारी के अनुसार- शिक्षक का इसी साल 30 नवंबर 2026 को रिटायर था। आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया- आरोपी शिक्षक को

गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10-15 बच्चों के अलग-अलग बयान लिए गए हैं, जिनका मेडिकल कराया गया है। पाँक्सो, एससी-एसटी एक्ट, आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी टीचर निलंबित मामले में चित्तौड़गढ़ जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही बेगू ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम मनस्वी नरेश ने बताया कि मामले की जांच के लिए चार लोगों की टीम बनाई गई है।

## पंचतत्व में विलीन हुए पद्मश्री अर्जुनसिंह शेखावत: बारिश के बावजूद अंतिम यात्रा में उमड़े शहरवासी



द मूवमेंट ऑफ इंडिया

अर्जुनसिंह शेखावत का आज नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। कल लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। शनिवार को पाली पंचायत समिति के सामने बने हिन्दू सेवा मंडल में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजन के साथ अंतिम यात्रा में एसडीएम पाली विमलेंद्र सिंह राणावत, सीओ सिटी उषा यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई, पूर्व

उपसभापति मूलसिंह भाटी, बीजेपी शहर अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह भाटी, परमेश्वर सिंह परिहार व कई शहरवासी शामिल हुए। पार्थिव देह को अर्जुनसिंह शेखावत के बेटों और पोतों ने मुखानि दी। इससे पहले सुबह 10 बजे शहर के पुराना हाउसिंग बोर्ड से अंतिम यात्रा निकाली गई। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और शहरवासी इसमें शामिल हुए। एसडीएम पाली विमलेंद्र सिंह राणावत और सीओ सिटी उषा यादव ने हिन्दू सेवा मंडल मोक्षधाम में पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।

## कांग्रेस सांसद और विधायक को जैसलमेर जाने से रोका: जैसलमेर-बाड़मेर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई



द मूवमेंट ऑफ इंडिया

जैसलमेर के बासनपीर में ऐतिहासिक छतरियों के निर्माण को लेकर हुए विवाद पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शनिवार को बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उममेदाराम बेनीवाला और बायतु विधायक हरीश चौधरी अपने समर्थकों के साथ बासनपीर के लिए निकले। दोनों अपने समर्थकों के साथ दोपहर करीब 2 बजे बाड़मेर-जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंचे। हालांकि यहां प्रशासन ने धारा 163 लागू की है। ऐसे में बासनपीर से 100 किलोमीटर पहले फतेहगढ़ में सांसद उममेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी को पुलिस ने रोक दिया। सांसद और विधायक दोनों बैरिकेडिंग के पास पहुंचे और पुलिस को रोकने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया और आगे जाने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों की पुलिस के साथ गहमागहमी हो गई। हरीश चौधरी ने पुलिस पर सरकार के साथ मिलकर असंवैधानिक काम करने के आरोप लगाए।

गौरतलब है कि हरीश चौधरी ने बासनपीर में गांधी राम धुन एवं सर्व धर्म प्रार्थना के आयोजन के लिए जैसलमेर प्रशासन से इजाजत मांगी थी लेकिन प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी। पुलिस ने जैसलमेर-बाड़मेर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। ऐसे में यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्यप्रदेश प्रभारी व बायतु विधायक हरीश चौधरी शनिवार को जैसलमेर के बासनपीर के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर करीब 2 बजे वे फतेहगढ़ पहुंचे। इससे पूर्व चौधरी ने कहा था- जिस तरह से हमारे थार के इस भाईचारे व अपणायत में जहर को घोला जा रहा है व इस इलाके में जिनके द्वारा नफरत फैलाई है हम शनिवार को मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में सत्ताधारी लोगों के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर जिस तरह से भेदभाव पूर्ण और एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

## सम्पादकीय

## भ्रम पैदा करती भाषा नीति

भारतीय बौद्धिक किसी भी मुद्दे पर लड़ते-उलझते रहने में मशगूल रहते हैं, उसके समाधान की चिंता से निर्लिप्त। कई मुद्दों पर वही तर्क-वितर्क दशकों से सुने जाते हैं, पर मुद्दे की स्थिति जस की तस या बिगड़ती जाती है। भाषा नीति इसका उदाहरण है। अभी अधिकांश विवाद ठाकरे बंधुओं की निंदा पर केंद्रित है। कुछ समय पहले तमिल नेता स्टालिन की फजीहत करने में ही ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई थी, जबकि भारत की भाषा नीति विगत आठ दशकों में क्या बनी और क्या हुई, इस पर उदासीनता ही रही है। ठाकरे बंधु हाल में राजनीतिक मंच पर

आए। उनका मात्र एक प्रदेश में थोड़ा प्रभाव है, किंतु इससे पहले क्या था? सच तो यह है कि स्वतंत्र भारत की भाषा नीति शुरू से बिन पतवार की नाव है। औपचारिक रूप से हिंदी 'राजभाषा' है, पर व्यवहार में हर क्षेत्र में सिर्फ अंग्रेजी का स्थान बढ़ता गया। यह उन नीतियों का परिणाम है, जिन्हें किसी अहिंदी नेता ने

नहीं बनाया। अंग्रेजी द्वारा हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं का क्रमशः विस्थापन किसी तमिल या मराठी राजनीति की देन नहीं है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। संविधान बनने के समय से ही उत्तर भारतीय, मुख्यतः हिंदी-भाषी नेताओं के निर्देशन में ही बहुत कुछ तय होता रहा है, पर उनके द्वारा बनी भाषा-नीति के नतीजों की कभी समीक्षा नहीं हुई कि वह किस उद्देश्य से बनी और परिणाम क्या हुए? भ्रमक भाषा नीति का दोष किसी एक नेता या दल को देना व्यर्थ है। संपूर्ण भारतीय नेतृत्व और बौद्धिक वर्ग भाषा नीति पर भ्रम का कारण और शिकार, दोनों रहा। इसका निराकरण करने में असमर्थ और अनिच्छुक भी। आज देश के छोटे-छोटे कस्बों में भी देखा जा सकता है कि अग्रगामी शिक्षा, रोजगार और व्यापार की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी न जानने वाले भी कामकाजी और व्यवस्थापक हो सकते हैं, पर सीमित स्तर तक। जिसे अपनी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता बढ़ाने की इच्छा है, जो सहज मानवीय आकांक्षा है, वह बिना अंग्रेजी प्रवीणता के विफल रहेगा। यदि कोई भारतीय केवल अंग्रेजी जानता हो और किसी भारतीय भाषा में एक नोट भी लिख न लिख सकता हो, तब भी उसे आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसा दुनिया के किसी अन्य महत्वपूर्ण देश में नहीं है। भारत में असली राजभाषा अंग्रेजी है। हिंदी को राजनीतिक कारणों से 'राजभाषा' कहकर प्रपंच चलाया जा रहा है। यही मराठी, तमिल या अन्य क्षेत्रीय नेताओं द्वारा हिंदी पर चोट करते रहने का भी कारण है। हिंदी का नाहक दोहरा अपमान होता है। इसकी तुलना में ब्रिटिश राज में भाषा-नीति अपेक्षाकृत पारदर्शी और यथार्थपरक थी। शासन की भाषा अंग्रेजी थी, पर केवल अपने लिए। देश के वृहत शिक्षा-संस्कृति क्षेत्र स्वायत्त थे। उसमें शासकीय दखलंदाजी नहीं थी। हर विषय के विद्वान ही उसके शिक्षण-प्रशिक्षण की सामग्री और विधान तय करते थे। ब्रिटिश राज में साहित्यिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास सचमुच समाज का काम था, सरकार का नहीं। स्वतंत्र भारत में उस क्रियाकलाप का ह्रास आरंभ हो गया। यह ह्रास स्वतंत्र भारत की अपनी नीतियों से हुआ। आज भारत में हिंदी ऐसी पटरानी है, जिससे अन्य सभी रानियां खार खाती हैं और रोज जली-कटी सुनाती हैं। पटरानी असहाय यह सब झेलने को लाचार है। हिंदी को झूठे राजत्व की दोहरी प्रवंचना से मुक्ति देना अच्छा होगा। तब कालक्रम में वह अपना सही स्थान पा लेगी। तब उसे अन्य भारतीय भाषाओं के नेताओं, बौद्धिकों की नाहक कटूक्तियों से छुटकारा मिलेगा। फिर उसे पहले जैसा सद्भाव मिल जाएगा। ब्रिटिश जमाने में हिंदी को राष्ट्रीय कामकाज की भाषा बनाने के सभी प्रयत्न अहिंदी नेताओं, ज्ञानियों ने किए थे। गांधीजी, राजगोपालाचारी, केएम मुंशी, टैगोर आदि महापुरुषों ने हिंदी की क्षमता और भूमिका पहचानी थी, किंतु यह तब था, जब देश में हिंदी वैसी ही एक भाषा थी, जैसी तमिल या तेलुगु थी। आज प्रशासन, शिक्षा और उद्योग व्यापार में अंग्रेजी की महत्ता वैसे भी अबाध बढ़ रही है। शंका हो तो 1963 और 1976 के राजभाषा कानून और नियम की तुलना करके देखें। फिर उसमें 1986, 2007 और 2011 में किए गए संशोधन भी।

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

# शाहपुरा के प्रतिनिधि मंडल ने की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

शाहपुरा राजेन्द्र खटीक।

शाहपुरा-शाहपुरा प्रतिनिधि मंडल ने की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात, संगठन के बारे में की विस्तृत चर्चा। युवा प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ब्लॉक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष जयंत जीनगर के नेतृत्व में मुलाकात की। गहलोत ने शाहपुरा को जिला बनाए जाने के निर्णय को निरस्त किए जाने पर सरकार पर तंज कसा।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और इसे जनभावनाओं के खिलाफ बताया। इस मौके पर अशोक



गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही शाहपुरा को फिर से जिला बनाया जाएगा। उन्होंने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए

कहा कि यह निर्णय विकास को रोकने वाला और जनता की अपेक्षाओं के विपरीत है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष

जयंत जीनगर, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन पोंड्रिक, शाहरुख खान भीमपुरा, प्रकाश धाकड़ मौजूद रहे।

## जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक में आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान

भीलवाड़ा । जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें प्रस्तुत कीं, जिन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

बैठक में जनसुनवाई के 100 से अधिक प्रकरण व सतर्कता के 4 प्रकरणों की सुनवाई की गई। जनसुनवाई के 100 से अधिक परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इनमें अतिक्रमण, रास्ते से संबंधित विवाद, जलभराव, गंदगी, जल निकासी, पेयजल कनेक्शन, राशन कार्ड चालू करवाने तथा पुलिस संबंधी शिकायतें प्रमुख रहीं। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को



शीघ्र, त्वरित एवं संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित जनसुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारित समयसीमा में निस्तारण की रैंकिंग में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पुनः प्रथम स्थान पर रहा है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा जिला प्रशासन की सराहना की गई। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

माध्यम से जुड़ते हुए अन्य जिलों को भी भीलवाड़ा से प्रेरणा लेने और त्वरित निस्तारण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर संधु ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्य करें और शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन

को राहत देना और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लें और मानवीय संवेदनाओं के साथ उसका निराकरण करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतिभा देवठिया जिला स्तरीय अधिकारीगण व उपखण्ड व ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

## कांकरोली में सोलफिट सोलर सोल्यूशन हब का विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने किया उद्घाटन

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

जेके सर्कल कांकरोली रोड में सांवरिया सोलफिट सोलर सोल्यूशन हब राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता को फाउंडर गंगाराम हुड्डा ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, छान लाल मैया, मोहनलाल भांबू, पार्षद मांगी लाल टांक, रमेश पहाड़िया, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह चुण्डावत, आमेट के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश वैष्णव सरदारगढ़, समाजसेवी शंकर लाल खींची, जगदीश प्रसाद, अनिरुद्ध गुर्जर, एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक



ललित खींचा, हेमंत गर्ग, स्नेहलता चौहान, दिनेश, नानालाल, दीपक, संजय, विपुल, मनोज, दिग्विजय सिंह, रामलाल आदि थे। सेंटर संचालक पुनीत खटीक, अशोक कुमार चौहान, कालु राम कीर, जितन चौहान ने अतिथियों

का स्वागत किया। पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक ने सोलर पैनल को उपयोगी बताते हुए कहा कि सोलर पावर का घर घर उपयोग होने से देश? आत्म निर्भर बनेगा। संचालक पुनीत खटीक ने बताया कि सोलफिट सॉल्यूशंस हब में एक

ही छत के नीचे सोलर से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सोलर इंस्टॉलेशन से लेकर बैंक ऋण संबंधी सेवाएं सब्सिडी सेवाएं उत्पादन की गारंटी एवं वारंटी दी जायेगी। सोलर के सभी टॉप ब्रांड यहां उपलब्ध रहेंगे।

## एससीओ में भारत!



विदेश मंत्रियों की बैठक का मकसद 30 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली एससीओ शिखर बैठक के एजेंडे एवं संयुक्त विज्ञप्ति को अंतिम रूप देना था। इसमें क्या प्रगति हुई, इस बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं दी गई है। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद को इस संगठन के एजेंडे में केंद्रित स्थल पर लाने की वकालत की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ध्यान दिलाया कि एससीओ का गठन आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए हुआ था। उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमले का जिक्र किया। कहा कि एससीओ को आतंकवाद के मसले पर समझौताविहीन रुख अपनाना चाहिए। चूंकि विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा विज्ञप्ति जारी नहीं होगी थी, इसलिए पिछले महीने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के समय जैसी कड़वाहट पैदा हुई थी, वैसा कुछ इस बार नहीं हुआ। विदेश मंत्रियों की बैठक का मकसद 30 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली एससीओ शिखर बैठक के एजेंडे एवं संयुक्त विज्ञप्ति को अंतिम रूप देना था। इसमें क्या प्रगति हुई, इस बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं दी गई है। मगर बाकी देशों की तरफ से जो कहा गया, वह इस बात का संकेत है कि इस मंच पर भारत का ठीक तालमेल नहीं बन पा रहा है। बेशक एससीओ जब बना, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का मुकाबला उसका प्रमुख मकसद था। लेकिन 2010 आते-आते आपसी आर्थिक सहयोग और इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ावा इसके एजेंडे में प्रमुखता पा गए। पिछले दशक के मध्य में एससीओ ने एक ट्रिपल पत्र स्वीकार कर लिया, जिसमें विकास और जुड़ाव को सुरक्षा का अभिन्न पहलू माना गया। 2023 में भारत के एतराज को नजरअंदाज कर बाकी सभी सदस्य देशों ने चीन की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति समर्थन जता दिया। 2024 में शिखर सम्मेलन के दौरान 2035 तक की एससीओ विकास रणनीति को मंजूरी दी गई, जिसमें विकास, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्धता जताई गई। हालांकि विदेश मंत्री ने कहा कि "सांभूहिक कल्याण" से जुड़े क्षेत्रों में भारत योगदान जारी रखेगा, लेकिन उन्होंने आतंकवाद को अपने भाषण का केंद्रीय बिंदु बनाया। इसका किटना अक्सर सदस्य देशों पर हुआ? यह जानने के लिए हमें शिखर सम्मेलन का इंतजार करना होगा। तब साझा घोषणापत्र में भारत की चिंताओं को पर्याप्त जगह मिलती है या नहीं, यह देखने की बात होगी।

## भारत में टेस्ला!



चीन से खराब रिश्तों के कारण इलेक्ट्रिक कार की निर्माता भारतीय कंपनियां कई मुश्किलें झेल रही हैं, जबकि एक अमेरिकी कंपनी ने चीनी पाट-पुर्जों के साथ अपनी कार को पूरी शान-ओ-शौकत से भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें अब भारत में उपलब्ध हैं। कंपनी के मालिक इलॉन मस्क बरसों से टेस्ला के लिए भारतीय बाजार को खुलवाने की कोशिश में थे। मगर उनहें कामयाबी तब मिली, जब उन्होंने अमेरिकी प्रशासन में अपनी प्रमुख हैसियत बनाई। यह दीगर बात है कि जब उनकी कंपनी का पहला शोरूम भारत में खुला, तब तक टकराव के कारण डॉनलड ट्रंप से प्रशासन से वे अलग हो चुके हैं। इस तरह भारत सरकार ने मस्क की टेस्ला और स्पेस-एक्स कंपनियों के लिए स्वागत-द्वार बनाते वक्त जो गणनाएं की होंगी, फिलहाल अमेरिका से रिश्तों में वे काम नहीं आएंगी। उल्टे मस्क ने आगे जाकर भारत में कारों की मैनुफैक्चरिंग शुरू की, तो वह ट्रंप की आंख में चुभने वाला एक कांटा बनेगा।ट्रंप खुलेआम इस पर अपनी नापसंदगी जता चुके हैं। फिलहाल, मस्क इस शर्त को मनवा कर आए हैं कि भारत में उनकी कंपनी मैनुफैक्चरिंग नहीं करेगी। यहां वह सिर्फ आयातित कारें बेचेगी। आरंभ में जो ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए हैं, उनमें ज्यादातर चीन में बने पाट-पुर्जों का इस्तेमाल होता है। ये अजीबोगरीब बात है कि चीन से खराब रिश्तों के कारण इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बीवाइडी एवं अन्य चीनी कंपनियों के भारत आने की राह में कड़ रूकावटें हैं, जबकि एक अमेरिकी कंपनी ने चीनी पाट-पुर्जों के साथ पूरी शान-ओ-शौकत से भारत में प्रवेश किया है। और वह भी उस समय, जब इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन जिन खनिजों पर निर्भर है, उनके निर्यात पर चीनी रोक के कारण भारतीय कंपनियां मुश्किल में हैं। अब टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों को बाजार के छोटे- लेकिन महत्वपूर्ण- हिस्से में टेस्ला की चुनौती का सामना भी करना होगा। अध्ययनों के मुताबिक भारत के कुल कार बाजार में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की कारों का हिस्सा सिर्फ 10 फीसदी है। फिलहाल टेस्ला की कारें 60 लाख रुपये से अधिक की पड़ेगी। मगर यह प्रीमियम क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक मुनाफा होता है। टेस्ला चीनी पाट-पुर्जों के साथ उसका लाभ उठाएगी। जबकि चीन से संबंधों में तनाव का नुकसान भारतीय कंपनियां भुगत रही हैं। क्या यह एक विडंबना नहीं है?

चैत्र नवरात्रि समाप्त होने के बाद मांस की दुकानें बंद कराने का जो अभियान उठर गया था वह एक अल्पविराम के बाद फिर शुरू हो गया है। सावन का महीना आते ही जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू हुई उसके रास्ते में खाने पीने की चीजों की दुकान चलाने वालों की पहचान करने का अभियान शुरू हो गया और इसके साथ ही मांस की दुकानें भी बंद कराई जाने लगीं हैं। हालांकि इस बार पिछली बार की तरह कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों को अपनी जातीय और धार्मिक पहचान दुकान के बाहर टांगने का आदेश नहीं दिया गया है। इस बार उनको क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनका पूरा नाम और पता लिखा होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कांवड़ियों को दुकान पर लगे बोर्ड से कोई कंपयुजन नहीं हो। वे क्यूआर कोड स्कैन करके दुकानदार का असली नाम और उसके धर्म का पता लगा सकेंगे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश से आगे यानी दिल्ली और हरियाणा में भी कांवड़ियों के रास्ते में आने वाली मांस की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। हालांकि दिल्ली में नगर निगम ने साफ कहा है कि किसी नियम के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन नियम एक तरफ और आस्था के नाम पर दादागिरी एक तरफ ! सावन के बाद फिर शारदीय नवरात्र में यही प्रक्रिया चलेगी। फिर दिवाली और छठ के समय भी अलग अलग इलाकों में इसे दोहराया जाएगा। कभी पर्यूपण पर्व के नाम पर तो कभी श्राद्धपक्ष के नाम पर मांस की दुकानें बंद कराई जाती हैं। कई धार्मिक स्थलों पर तो स्थायी रूप से मांस की दुकानें बंद कराई जा चुकी हैं और कई जगहों पर बंद कराने के प्रयास चल रहे हैं। यह काम धार्मिक भावना आहत होने के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करने वालों को हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह काम करते हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया में मूर्खानेपूर्ण प्रलापों के जरिए कथावाचकों और इंग्लूएसर्स ने मांसाहार के खिलाफ जमीन तैयार कर दी है और अब इसका राजनीतिक लाभ लेने का समय आ गया है। उनको यह भी लगता है कि मांस की दुकानों सिर्फ मुस्लिम क्लबते हैं इसलिए उनको बंद कराने से मुसलमानों को नुकसान होगा और हिंदुवादी राजनीति चमकाने में सुविधा होगी। कुछ समय पहले एक छुटभेया नेता यह काम करते थे।जिनको पार्श्व या विधायक आदि की टिकट चाहिए होती थी और कोई राजनीतिक पहचान नहीं होती तो वे इस तरह के काम करते थे। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया में शाकाहार की महानता बताई जाने लगी और मांसाहार को धर्म विरुद्ध ठहराया जाना लगा। यह एक संस्थागत प्रयास में बदल गया, जिसमें देश की जनता को धार्मिक बना कर अनंतकाल तक उन पर राज करने की मंशा रखने वाले सांस्कृतिक संगठन, उसकी पार्टी और उसके अनुषंगी संगठन शामिल हो गए। उनको इस विषय के मेरिट यानी गुण दोष से कोई



लेना देना नहीं है। इसमें उनको राजनीतिक लाभ होता दिख रहा है इसलिए वे यह काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मांस की दुकानें बंद कराने वाले केंट्री फ्रायड चिकन यानी केएफसी के आउटलेट नहीं बंद कराते हैं। वे प्रोसेस्ड फूड बेचने वाली दुकानों को बंद नहीं कराते हैं, जहां प्रोजेज आइटम्स बेचे जाते हैं। उनको पता है कि इनमें से ज्यादातर दुकानें गैर मुस्लिमों की हैं और उनमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जो शाकाहार की महानता का प्रचार करते हैं। आखिर मांस निर्यात से लेकर चमड़े के कारोबार तक अनेक ऐसे लोग शामिल हैं। सोचों, आस्था कितनी लचीली है ! सो, पहला निकर्ष तो यह बनता है कि मांस की दुकानें बंद कराने या कांवड़ियों की यात्रा के रास्ता में पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के उछे प्रार्थमिक मंशा मुसलमानों को निशाना बनाने की है। उसमें झटका मीट बेचने वाले कुछ हिंदू, सिख भी अगर प्रभावित होते हैं तो उनको कोलेटरल डैमेज माना जा सकता है। ध्यान रहे हिंदुओं के प्रिय नेताओं में से एक गिरिराज सिंह झटका मीट खाने के लिए हिंदू समाज को काफी समय से प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहरहाल, हिंदू धर्म की मान्यताओं या परंपराओं के प्रति अनजान जो लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह अभियान चला रहे हैं उनके अलगा एक समूह ऐसा भी है, जो सुनियोजित तरीके से शाकाहार और हिंदू धर्म को एकाकार करने में लगा है। उनको हिंदू धर्म की विविधता और उसकी परंपराओं के बारे में पता है लेकिन वे उस विविधता को खत्म करके हिंदुओं की एक विशिष्ट पहचान बनाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि मांसाहार ईसाई और इस्लाम धर्म की पहचान है और इसलिए शाकाहार हिंदू धर्म की पहचान बने। तमाम हिंदुवादी संगठनों और कथावाचकों के जरिए इसका प्रचार किया जा रहा है। गांवों, कस्बों और शहरों में कथावाचकों के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिसमें

वे शाकाहार का महत्व समझा रहे हैं। उसे श्रेष्ठ बता रहे हैं और मांसाहार त्यागने की अपील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस तरह वे हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं लेकिन असल में वे हिंदू धर्म की जड़ खोखली कर रहे हैं। जो लोग नवरात्रों में देवी की पूजा के नाम पर मांस की दुकानें बंद कराते हैं क्या उनको पता नहीं है कि इस देश के अनेक हिस्सों में देवी को प्रसाद के तौर पर मांस चढ़ाया जाता है? क्या वे नहीं जानते हैं कि देश के बड़े हिस्से में देवी की पूजा बिना बलि के पूर्ण नहीं होती है? हो सकता है कि छुटभेया नेता नहीं जानते हों लेकिन जो सांस्थायिक प्रयास कर रहे है वे इससे परिचित होंगे। फिर भी अपनी राजनीति साधने के लिए वे इसे बढ़ावा देते हैं। इतनी मुश्किल से इस देश में शैव व वैष्णव के और वैदिक व तान्त्रिकों के विवाद सुलझाए गए हैं लेकिन अब एक बार फिर पूरे देश को वैष्णव बनाने का अभियान छेड़ दिया गया है। ऐसी आसथाती सोच दुनिया के किसी दूसरे धर्म में नहीं दिखती है। इस्लाम में कुर्बानी की प्रथा है तो कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है कोई संगठन बकरीद के मौके पर कुर्बानी रूकवाने या मांस की दुकानें बंद करवाने निकल पड़ा है। अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे के दिन एक टर्की को राष्ट्रपति आजाद कराते हैं और उसके बाद करोड़ों टर्की मार दिए जाते हैं। लेकिन कौन अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस परंपरा को बंद कराने नहीं जाता है। बौद्ध धर्म ने ऐसे समय में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जब देश में पशुओं के जरिए ही खेती होती थी, वे अर्थव्यवस्था का सबसे अहम टूल थे और उनकी संख्या कम होती जा रही थी। तब उनका बचाने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया लेकिन उस समय भी मांसाहार पर रोक नहीं लगाई गई। मरे हुए पशुओं का मांस खाने पर कभी पाबंदी नहीं रही। आज तो तमाम बौद्ध देशों में सहज भाव से मांसाहार प्रचलित है। उन्होंने इसे धर्म का मुद्दा नहीं बनने दिया है। यहुदियों का एकमात्र देश इजराइल प्रति व्यक्ति मांस की खपत में दुनिया में नंबर एक है। दुनिया भर के देशों में खाने पीने को निजी पसंद माना जाता है और उस आधार पर व्यक्ति की श्रेष्ठता का आकलन नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की राजधानी में "प्राउड टू बी वेजिटेरियन" के बड़े बड़े हॉर्डिंग्स लगे दिखाई देते हैं। सोचें, इसमें क्या प्राउड करने की बात है कि आप शाकाहारी हैं। असल में यह आपका गर्व नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की भावना है। क्या हो अगर इसके आगे कोई आए और "प्राउड डू बी वीगन" की हॉर्डिंग लगा दे और उसके आगे कोई इस बात पर गर्व करे की वह सिर्फ फलाहार करता है और उससे भी आगे का कोई आ जाए कि वह भी पकवान है और इसलिए वह सबसे महान है। इस तरह की बातें और काम करने वाले अपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, जिनके पास न तो इतिहास की दृष्टि है और न धर्म की समझ है।

# सड़कों पर चलने वाले आन्दोलन ही सफल होते हैं!

सामान्य जनता को कुछ हद तक परेशान करने वाले आन्दोलन सफल होते हैं, यह चौकाने वाला तथ्य है, क्योंकि ये नतीजे जनता और मीडिया के विचारों के बिलकुल विपरीत हैं। पर, 70 प्रतिशत से अधिक आन्दोलन विशेषज्ञों ने इसी तरीके को किसी आन्दोलन की सफलता का सबसे बड़ा करण बताया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि सामाजिक आन्दोलनों के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है और इसका विश्लेषण कभी व्यापक तरीके से नहीं किया जाता। 9 जुलाई को सभी प्रमुख ट्रेड संगठनों ने सम्मिलित तौर पर बीजेपी सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी हड़ताल और धरण प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शन नई दिल्ली के जंतर-मंतर रोड पर भी किया गया था। बहुत दिनों बाद किसी प्रदर्शन में भीड़ नजर आ रही थी, प्रेस के भारी-भरकम कैमरे चित्र खींच रहे थे और अनेक डिजिटल न्यूज आउटलेट के प्रतिनिधि रेपोटींग करते नजर आ रहे थे। शापद बहुत दिनों बाद एक परंपरागत प्रदर्शन नजर आ रहा था। हवन ने लहराते लाल झंडे, किसान-मजदूर जैसे प्रदर्शनकारी, और नारों के साथ डफली की आवाज – नारे भी जिन्दाबाद, वापस लो-वापस लो, होश में आओ और नहीं चलेगी-नहीं चलेगी जैसे परंपरागत अवैजज। नारों में किसान-मजदूरों की भी संकीर्णता किया जा रहा था। अस्पर्श यह था कि आजकल के विरोध की परंपरा से उलट किसी व्यक्ति-विशेष पर कोई ग़हरा नहीं था, बस नीतियों का विरोध था। लहराती तख्तियां पर नारे स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखे गए थे और युवाओं की भागीदारी अच्छी-खासी थी। यह एक अयवाद था, क्योंकि हमारे देश में तो अब आंदोलनों और प्रदर्शनों की परंपराटी ही खत्म होती जा रही है। बीजेपी सरकार में गरीबों को गरीबी, भूखों को भूख

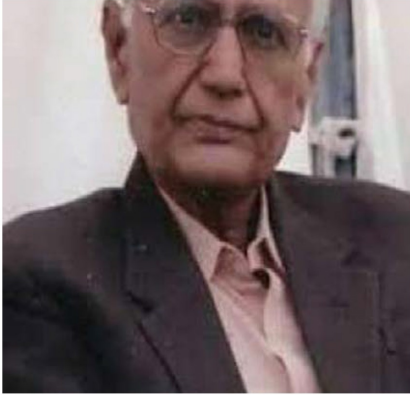


और बेरोजगारों को बेरोजगारी अब प्रभावित नहीं करती – सबकी समस्याएं अब सत्ता और मीडिया के ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, झुठ, बेमानी और बेशर्मी से ही खत्म हो जाती हैं। आंदोलनों पर नजर रखने वालों के अनुसार ऐसे अहिंसक आन्दोलन जो सामान्य जनता की रोजमर्रा की ज़िन्दगी को प्रभावित करते हैं – जैसे सड़कों को अवरुद्ध करना, सरकारी कार्यालयों में प्रवेश को रोकना, सांस्कृतिक या खेल स्मारकों में बाधा पहुँचना, बाजारों का मार्ग अवरुद्ध करना – जनता, सत्ता और मीडिया की नजर में भले ही बेकार के हों, पर आन्दोलन विशेषज्ञों की नजर में ऐसे तरीके ही आन्दोलनों को सफल बनाते हैं। अधिकतर विशेषज्ञों के अनुसार किसी आन्दोलन को सफल बनाने का यही सबसे प्राचीनी तरीका है। आन्दोलन विशेषज्ञों का यह सर्वेक्षण यूनाइटेड किंगडम स्थित आन्दोलनों पर अध्ययन करने वाली संस्था सोशल चेंज लैब ने करवाया है। स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखे गए थे और युवाओं में सवाल पूछा था – किसी आन्दोलन को सफल बनाने का सबसे प्राभावी तरीका क्या है? हमारे देश के लोगों को आन्दोलनों के बारे में समझना करना है, क्योंकि यहाँ सामाजिक या आर्थिक विषयों पर

आन्दोलन ही नहीं होते। हमारे देश में पिछले 50 वर्षों के दौरान तीन बड़े और राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन हुए हैं – जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन, अन्ना हजारे का आन्दोलन और किसानों का आन्दोलन। इसमें से पहले दो आन्दोलन कांग्रेस के सत्ता पर एकाधिकार, निरंकुश सत्ता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे। दोनों ही आन्दोलनों के साथ देश की जनता जुड़ी और इन आन्दोलनों की शुरुआत भी एक स्पष्ट उद्देश्य को लेकर हुई। फिर, ये आन्दोलन सत्ता पर काबिज होने के लिए चलाने जाने लगे। जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के बाद हिन्दू राष्ट्र और सामाजिक ध्रुवीकरण वाली बीजेपी सत्ता का एक हिस्सा बनी और अन्ना हजारे के आन्दोलन के बाद तो पूरी तरह सत्ता पर काबिज हो गई होगी। इन दोनों आन्दोलनों के जो उद्देश्य थे, और जनता जिन समस्यायों से छुटकारा पाना चाहती थी – वही समस्याएं अब पहले से भी व्यापक बनकर जनता के सामने खड़ी हैं। कुल मिलाकर आन्दोलनों का नाटक करने वाले और सड़कों पर संचर्य का दिखावा करने वाले सभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं और एक जीवंत प्रजातंत्र को निरंकुश सत्ता में बदल दिया। जाहिर है, ऐसी निरंकुश सत्ता के काबिज होने के बाद आन्दोलनों को कुचला गया, झुटे आशवासन देकर उन्हें खत्म कराया गया और अब तो जनता आन्दोलन करना ही भूल गयी है। हमारे देश में तो जिन आन्दोलनों को सफल कहा जा सकता है, उन आन्दोलनों का असर ही उल्टा हो गया। एक साल से भी अधिक चले किसान आन्दोलन के बाद भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा सरकारी तौर पर और सामाजिक तौर पर भी किसान पहले से अधिक उपेक्षित हो

गए। पहले कभी-कभी किसानों की समस्याओं से सम्बंधित कुछ समाचार प्रकाशित भी होते थे, पर आन्दोलन खत्म होने के बाद तो मीडिया ने भी उनको भुला दिया। फ्रांस में 17 वर्ष के बच्चे की मृत्यु पुलिस वालों की गोली से हो जाती है तो पूरा फ्रांस सड़कों पर उतर जाता है। दूसरी तरफ हमारे देश में किसी को पुलिस वाले मार डालते हैं, तब सत्ता-सम्पर्क जर्जन मानते हैं, मीडिया उसे आतंकवादी और देशद्रोही करार देती है, सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के बारे में हिंसा भड़काई जाती है। सत्ता पुलिसवालों को आल्टी हत्या के लिए बढ़ावा देती है और इन सबके बीच देश की बेरोजगार और भूखी जनता अगले शाम पेट भरने के इंतजाम में व्यस्त रहती है। हमारे देश में हरेक आन्दोलनकारी, भले ही वह देश का नाम बढ़ा रहा हो, सत्ता और पुलिस को नजर में देशद्रोही ही है। सामाजिक बदलाव की संभावना वाले आन्दोलन अधिक सफल होते हैं। भले ही ऐसे आन्दोलन को समाज का कोई भी एक पड़ित वर्ग शुरू करे पर धीरे धीरे सामाजिक बदलाव की संभावना का आकलन कर समाज का हरेक वर्ग ऐसे आन्दोलन से जुड़ चुका है। दरअसल यह काम आन्दोलनों पर सारे अध्ययन यह मान कर किये गए हैं कि लोग केवल भावनात्मक तौर या फिर आवेश से आन्दोलन से जुड़ते हैं, पर स्टैनफोर्ड पब्लिक स्कूल ऑफ बिजनेस के समाजशास्त्रियों द्वारा किये गए अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जब सामान्य लोगों को महसूस होता है कि किसी आन्दोलन का व्यापक असर समाज पर पड़ेगा, तब ऐसे आन्दोलनों से अधिक लोग जुड़ते हैं और ऐसे आन्दोलन लम्बे समय तक चलते हैं। इस अध्ययन को पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

# हमारे दतिया के एक पब्लिक इंटलेक्चुअल!



दूसरी भारतीय भाषाओं — बंगाली, मलयालम, तेलुगु, मराठी — में वहां के साहित्यकार अपने छोटे शहरों में रहते हुए भी राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं। मगर हिन्दी में जो दिल्ली नहीं आया, उसकी प्रतिभा और काम उतना सामने नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। पांडेय जी इसी त्रासदी के मूक नायक रहे — एक पौडेय जी जो राष्ट्रीय पहचान के साथ उसका लाभ उठाएगी। जबकि चीन से संबंधों में तनाव का नुकसान भारतीय कंपनियां भुगत रही हैं। क्या यह एक विडंबना नहीं है?

स्मृति- डॉ. केबीएल पांडेय अब ऐसा होता नहीं कि शहर में एक शून्य हो जाए और वह किसी नेता या किसी दूसरे क्षेत्र की अजीम हस्ती के जाने से नहीं, बल्कि एक साहित्यकार के जाने से हो! मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी दतिया में डॉ. केबीएल पांडेय के जाने से ऐसा ही हुआ। अभी रविवार, 13 जुलाई को पांडेय जी, जिन्हें हम हमेशा 'सर' ही कहते थे, नहीं रहे। और हम ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड, ग्वालियर-चंबल संभाग में हर जगह उन्हें सम्मान के साथ 'सर' ही कहा जाता था। इतना सम्मान, ख्याति और लोकप्रियता किस लिए?

प्रार्थिक परिचय तो एक कॉलेज शिक्षक का था — जो दतिया कॉलेज में हिन्दी पढ़ाते थे। मगर 'सर' इसके बाहर भी अपना असर रखते थे। साहित्य में था ही, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी उनका गहरा प्रभाव था। सदा मुस्कुराते रहने वाले, कभी किसी से आग्रिज न बोलने वाले 'सर' अपनी प्रभावी शक्तियत और सामाजिक संवेदना के कारण उन लोगों में भी लोकप्रिय थे जो उनसे सीधे नहीं मिल पाते थे, बल्कि सभा-समारोहों में उन्हें सुन लेते थे। उनकी वक्तुत्व कला बहुत प्रभावशाली थी। जब बोलते थे तो लगता था, सुनते रहो। 26 जनवरी और 15 अगस्त के सरकारी समारोहों में उनकी आवाज और प्रसुति के आकर्षण में बहुत लोग कार्यक्रम स्थल की ओर खिंचे चले आते थे। आम लोगों के लिए विद्वता के अलग मायने होते हैं। शुष्क बुद्धिजीवी उन्हें प्रभावित नहीं करते। वह ज्ञान-चर्चा कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है — अकादमिक क्षेत्रों तक। मगर ज्ञान, विचार और संवेदना का असली अर्थ तब है जब वह आम जनता तक पहुंचे। पांडेय जी उसी श्रेणी के बौद्धिक थे। जिसे कहते हैं पब्लिक इंटलेक्चुअल — जो अपनी अकादमिक दुनिया से बाहर आकर लोगों से सीधा संवाद करते हैं। यहाँ हम नोम चॉम्स्की का नाम नहीं लेंगे — वे तो जन बुद्धिजीवियों में विश्व के सबसे ऊपर माने जाते हैं। हिन्दी के कुछ लोगों का नाम लेगी। मगर चॉम्स्की याद इसलिए आए कि उनका पहला काम भाषा विज्ञान में है। और पांडेय जी का भी भाषा पर बहुत काम है — खासतौर से बुंदेली पर। तो हिन्दी में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जैसी भूमिका हरिशंकर परसाई और राजेन्द्र यादव ने निभाई, ग्वालियर में प्रकाश दीक्षित ने, वैसी ही बुंदेलखंड में पांडेय जी ने निभाई। एक सम्मानित सार्वजनिक शक्तियत का असर कितना होता है, इसका एक उदाहरण बताते हैं। बात 1975 की शुरुआत की है। एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था। सारे बड़े कवि आए हुए थे। उन दिनों शरद जोशी ने नया-नया क (व्यायं) मंच से पढ़ना शुरू किया था। वे भी थे। नीरज, जो उस समय अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, कविता पढ़ रहे थे। संचालन 'सर' (पांडेय जी) कर रहे थे। 1975 का वह समय राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था। बहुत कम युवा और छात्र ऐसे थे जो जेपी आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थों को समझ रहे थे। कुछ ही समय बाद जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से सेना और पुलिस को सरकार के आदेश नहीं मानने का आह्वान किया था — जिसके बाद इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। तो नीरज ने कविता पढ़ना शुरू किया — "ओ

दिल्ली जाने वाले राही, कह देना इंदिरा गांधी से"। हमने आवाज लगाई — "यह नहीं चलेगा!" हम छात्र नेता थे। हमारे साथ के लड़के भी चिल्लाए। उन दिनों नीरज जेपी आंदोलन का समर्थन करते हुए यह कविता सुनाते थे। लड़कों के शोर के बाद मंच पर खामोशी छा गई। मगर तभी एक आवाज गुंजी — "शकौल!" और शकौल खामोशी हो गए। यह आवाज थी 'सर' की। और उसमें न आदेश था, न रोष। एक साधारण, शालीन आवाज। मगर उसका असर इतना था कि बिना एक शब्द और बोले, हम शांत हो गए। नहीं तो छात्रों की राजनीति में ऐसा होता नहीं है — वहां इसे 'सरेरड' करना माना जाता है। मगर यह एक सार्वजनिक बौद्धिक का पुण्य प्रताप होता है, जिसके सामने बाकी मूल्य पैमाने बौने हो जाते हैं — और सम्मान से केवल सिर झुका लिया जाता है। लिखने को बहुत कुछ है, मगर चलते हैं वहां से जहां से पांडेय जी अपनी शुरुआत बताते हैं — आरएसएस से। शाखा में नियमित रूप से जाने वाले स्वयंसेवक। इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान रज्जू भैया (प्रो. राजेन्द्र सिंह, जो बाद में संघ प्रमुख बने) से बहुत प्रभावित। मुरली मनोहर जोशी और गिरिराज किशोर से भी निकट संबंध। लेकिन बाद में साहित्य की प्रगतिशील धारा से जुड़ावा। यह यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पांडेय जी के ही शब्दों में — परिवर्तन समाजपरक सोच से आया। पहले अंग्रेजी में एमए, फिर हिन्दी में एमए और पीएचडी। इलाहाबाद में ही निराला थे। उनका 'तोड़ती पत्थर', 'अबे सुन वे गुलाब', और प्रेमचंद का 'गोदान' — इन रचनाओं ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वह एक वीडियो इंटरव्यू में कहते हैं — "गोदान में होरी की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर जो बोझ आता है, उसने मेरी पूरी धारा बदल दी।" मजदूर-किसान की कठिनाइयों ने उन्हें प्रगतिशील कविता को आम मोड़ दिया। शोषण दिखने लगा। संवेदना जगने लगी। यह एक बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया थी। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध कविता है — "अब कहाँ संवाद की संभावनाएँ, प्रश्न तक की जब हमें अनुमति नहीं है!" बुंदेलखंड के किसान पर उनकी कविता कहती है: "फसल अच्छी हुई, पूरा परिवार खुश है। मगर — मंडी से लौटकर लगाने ये कितने सपने सच हैं, कितने खाम-खाली में!"

पांडेय जी मूलतः कवि थे। लेकिन काम उनका सबमें था — इतिहास, शोध, आलोचना, अनौपचारिक जन-शिक्षण से लेकर औपचारिक शिक्षण तक। मगर कविता में वे सबसे मुखर अंदाज में सामने आते थे। आज के हालात पर उनकी पंक्तियाँ देखें: "सच कहीं दरबान सा बाहर खड़ा है, झुठ मसनद से टिका है।" कविता के अलावा, जिस क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा और गंभीर काम किया, वह था — शोध। प्रसिद्ध लेखिका और बुंदेलखंड से ही ताल्लुक रखने वाली उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा ने कहा था — "काश मेरे शोध-गुरु पांडेय जी होते।" शोध के प्रति उनकी गंभीरता को एक प्रसंग से समझिए। ऊपर हमने ग्वालियर के विद्वान प्रकाश दीक्षित का का जिक्र किया, जिनका पांडेय जी बहुत सम्मान करते थे। मगर हमारा रिश्ता प्रकाश जी से कुछ उनकी उदारता और कुछ वैचारिक साम्यता के कारण मित्रवत था। तो 'सर' हंस कर कहते थे — "तुम्हारे दोस्त ने कितनों को डॉक्टर बना दिया?" — मतलब पीएचडी करवा दी। बात एक हद तक सही थी। प्रकाश जी उदारतापूर्वक पीएचडी करवा देते थे। पांडेय जी कड़े अनुशासन की मांग करते थे। यह मित्रवत तंज था — मगर शोध की गरिमा के प्रति उनका आग्रह उसमें स्पष्ट झलकता था। वह हिन्दी की दुनिया ही अलग थी। मगर एक बात साफ है — हिन्दी में बड़ी-बड़ी प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए सामने नहीं आ पाई क्योंकि वे अपने शहर से बाहर नहीं निकली। प्रकाश जी को भी मुम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर दिल्ली की पत्रकारिता तक कई ऑफर मिले। मगर वे कहते थे — "ग्वालियर में तो मैं घर से निकलकर कौकी हाऊस जाता हूँ, तो कितने लोग नमस्कार करते हैं — वहां कौन पहचानेगा?" यही हाल पांडेय जी का था। दतिया में जब वे घर से निकलकर बाजार आते थे तो हर तरफ से नमस्कार-नमस्कार होता था। यही आमीयता, यही पहचान उन्हें प्रिय बनाती थी। दूसरी भारतीय भाषाओं — बंगाली, मलयालम, तेलुगु, मराठी — में वहां के साहित्यकार अपने छोटे शहरों में रहते हुए भी राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं। मगर हिन्दी में जो दिल्ली नहीं आया, उसकी प्रतिभा और काम उतना सामने नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। पांडेय जी इसी त्रासदी के मूक नायक रहे — एक ऐसे पब्लिक इंटलेक्चुअल, जिन्होंने मंच, माइक, कविता, शोध और स्मृति — सबको एक गहरी मानवीय भाषा में बाँध दिया।

## टी20 ब्लास्ट में गेंदबाजों के लिए काल बने जॉर्डन काॅक्स, 22 बाउंड्री के साथ ठोका तूफानी शतक



एजेंसी नई दिल्ली

टी20 ब्लास्ट में एसेक्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्डन काॅक्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से धूम मचा दी। जॉर्डन काॅक्स ने हैमशायर के खिलाफ 60 गेंदों में 231.67 की स्ट्राइक रेट से 139 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। अपनी इस पारी में उन्होंने 11 छक्के और 11 चौके भी लगाए। जॉर्डन ने सिर्फ बाउंड्री से अपने 100 रन पूरे किए। इस तरह जॉर्डन मुकाबले में हैमशायर के गेंदबाजों के लिए काल बन कर बरसे। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के कारण ही एसेक्स को टीम 4 विकेट से दमदार जीत हासिल की। एसेक्स के लिए बल्लेबाजी में काॅक्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन जैम्स फुलर के पहले ओवर में 19 रन बटोरने के बाद उन्होंने गेंदबाजों की जो खबर ली उसके बाद हैमशायर के गेंदबाज दहशत में आ गए।

फुलर के बाद काॅक्स ने बेनी हॉवेल के भी पहले ओवर में 19 रन बटोरे और आठवें ओवर के अंत तक 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। काॅक्स ने हॉवेल के दूसरे ओवर में भी कोई रहम नहीं दिखाया और लगातार तीन छक्के जड़कर 80 रन तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर अपना शतक पूरा किया। अंतिम के तीन ओवर में एसेक्स को जीत के लिए 41 रन की जरूरत थी, सेकिन काॅक्स के तूफान के आगे हैमशायर की गेंदबाजों बौनी साबित हुईं और लक्ष्य को पूरी तरह से आसान बना दिया। एसेक्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी। अंतिम ओवर में भी काॅक्स ने पहली दो गेंदों पर दो छक्के जड़कर शानदार अंदाज में मैच खत्म किया और एसेक्स के लिए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस सीजन में एसेक्स के लिए यह जीत बेशक शानदार रही हो, लेकिन टीम के पूरे प्रदर्शन को देखें तो वह कुछ खास नहीं रहा है।

## टीम इंडिया कभी नहीं जीत पाती 2011 वनडे विश्व कप, युवराज सिंह को लेकर इस एक फैसले से बदल गया सब कुछ

एजेंसी नई दिल्ली

पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने लिमिटेड ओवरों के कई बड़े टूर्नामेंट टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे। खास तौर से युवराज सिंह को 2011 वनडे विश्व कप में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है, लेकिन इस विश्व कप के लिए उनका टीम में चयन निश्चित नहीं था। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य कोच गैरी कस्टन ने बताया कि युवराज का टीम में चयन को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उनका स्क्वाड में चुना जाना तय नहीं था, लेकिन कस्टन और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने युवराज सिंह का सपोर्ट किया और उन्हें विश्व कप की टीम में शामिल किया गया। धोनी और कस्टन का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और युवराज सिंह भारतीय टीम की जीत के नायक रहे। पूरे टूर्नामेंट में युवराज सिंह ने गेंद और बैट दोनों से अपना दम दिखाया। बल्लेबाजी में उन्होंने 362 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में 15 विकेट भी लिए थे। यही कारण है कि युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। युवराज सिंह



का यह शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। किसी भी हाल में युवराज को टीम में चाहते थे कस्टन रेंडिफ डॉट कॉम के साथ एक बातचीत में कस्टन ने युवराज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा उनकी बल्लेबाजी देखना पसंद था। भले ही कभी-कभी निराशा होती थी। कस्टन ने कहा, 'मैं हमेशा युवराज को बहुत पसंद करता था। वह कभी-कभी मुझे बहुत परेशान करता

था, लेकिन मुझे वह बहुत पसंद था। वह अच्छा था। मैं बस चाहता था कि वह हर समय रन बनाए क्योंकि उसे बल्लेबाजी करते देखना अद्भुत था।' कस्टन ने मानसिक कंडीशनिंग कोच पैडी अटन को युवराज को शारीरिक और मानसिक रूप से टूर्नामेंट के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया। कस्टन ने कहा, 'युवराज को अपनी एक मंजिल तय करनी थी और इसका श्रेय पैडी को जाता है। पैडी ने युवराज को तैयार करने के लिए बहुत काम किया। युवराज ने खुद विश्व कप की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए।' 2011 वनडे विश्व कप में युवराज सिंह के आंकड़े को देखें तो वह किसी भी भारतीय बल्लेबाज से बेहतर थे। उन्होंने आठ पारियों में बल्लेबाजी की जिसमें 90.50 की औसत से 362 रन बनाए, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल थे। उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया जहां उन्होंने 123 गेंदों पर 113 रन बनाए। उन्होंने इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी महत्वपूर्ण पारियां खेलीं थीं।

## जितेश शर्मा और रसिख सलाम ने बदल ली अपनी टीम, नए सीजन में अब यहां मचाएंगे दोनों धमाल

एजेंसी नई दिल्ली

विदर्भ और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेटकीपर जितेश शर्मा और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिख सलाम दार आगामी घरेलू सत्र में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के साथी और बड़ौदा के कप्तान कृपाल पांड्या की मदद से यह बदलाव किया है। जितेश ने पिछले सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्राफी में विदर्भ की कप्तानी की थी और उन्हें क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन 2024-25 रणजी ट्राफी में उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। जितेश भारत के लिए 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वह आईपीएल 2025 चैंपियन आरसीबी के लिए एक शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे। वहीं तेज गेंदबाज रसिख ने पांच फस्ट क्लास मैचों में 25.23 की औसत से 13 विकेट लिए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 10 मैचों में 37.46 की औसत और 5.80 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए हैं। उन्होंने 36 टी20 मैचों में भी भाग लिया है जिसमें उन्होंने 23.13 की औसत और 8.52



की इकॉनमी रेट से 45 विकेट लिए हैं। रसिख ने अक्टूबर 2018 में 2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर के लिए अपना लिस्ट ए डेब्यू किया था और उसी साल 30 दिसंबर को अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। भारत

इंडियंस के लिए खेला है। वह 2017 में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे जिसमें ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में अब वह नई घरेलू टीम के साथ एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।

### इस बार फिर 90 पार! लंदन डायमंड लीग में जानें कब और कहां देव सकते हैं नीरज चोपड़ा का लाइव एक्शन

एजेंसी नई दिल्ली

भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लीग में शानदार जीत के बाद वह अब लंदन डायमंड लीग में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। नीरज चोपड़ा इस इवेंट में दुनिया के टॉप जैवली श्रोअर के साथ टक्कर लेंगे। 19 जुलाई को आयोजित होने वाले लंदन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के अलावा जर्मनी के जूलियन वेबर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, और केन्या के जूलियस येगो जैसे धुरंधर शामिल होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन लंदन स्टेडियम में होने जा रहा है। नीरज चोपड़ा के लिए लंदन डायमंड लीग का यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिस डायमंड लीग में अपनी जीत के बाद वह अपनी लय को बरकरार रखना चाहेंगे और अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देना चाहेंगे। इस सीजन में नीरज ने पहले ही दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर के श्रो के साथ अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन तब उन्हें जूलियन वेबर से हार का सामना करना पड़ा था। पेरिस में वेबर को हराकर



नीरज ने हिसाब चुकता किया और अब उनका लक्ष्य लंदन में भी टॉप पर रहना होगा। लंदन डायमंड लीग का आयोजन 19 जुलाई 2025 को हो रहा है। इस इवेंट में भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा

हैं। ऐसे में फैसले के लिए यह जानना जरूरी है कि नीरज चोपड़ा का लंदन डायमंड लीग में यह इवेंट कब और कहां देखा जा सकता है। दरअसल लंदन और भारत के समय में लगभग 4.5 घंटे का अंतर है। ऐसे में नीरज चोपड़ा का ये इवेंट भारतीय समयानुसार देर रात लगभग 1:00 से 2:00 बजे के बीच शुरू होने की संभावना है। वहीं नीरज चोपड़ा के इस इवेंट को लाइव देखे जाने की बात है तो इसका लाइव स्ट्रीमिंग वांडा डायमंड लीग यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इसके अलावा वांडा के फेसबुक पेज पर भी इस इवेंट को लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।

## वया रोहित शर्मा पर डाला गया था टेस्ट से संन्यास के लिए दबाव पूर्व सिलेक्टर का हैरान करने वाला खुलासा



एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौर से ठीक पहले लाल गेंद क्रिकेट संन्यास का ऐलान कर दिया था। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान था। वहीं अब टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर जतिन परांजपे ने रोहित शर्मा को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। जतिन का मानना है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए आखिरी टेस्ट से बाहर नहीं होते तो भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी बराबर कर सकता था। रोहित शर्मा ने उस पांच मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट से खुद को बाहर कर लिया था, क्योंकि उन्होंने खेले गए तीन टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन किया था। तत्कालीन भारतीय कप्तान सिर्फ 31 रन ही बना पाए थे। जब सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में थी तो रोहित ने अंतिम टेस्ट से हटने का फैसला किया। ऐसे में उनकी जगह जसप्रीत बुमराह ने टीम की कप्तानी की थी। जतिन परांजपे ने में कहा, 'मुझे याद है कि वह भारत के लिए टेस्ट

क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और हमारी यह बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि जतिन मैंने लाल गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। आप यह कैसे कर सकते हैं कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है?' मुझे संदेश मिल गया था और मुझे उम्मीद थी कि वह यही कहेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'रोहित ने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट के लिए जीते हैं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में और बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे लगता है कि वह खुद भी सबसे पहले यही कहेंगे। मुझे थोड़ी निराशा हुई कि उन्होंने सिडनी में खुद को बाहर करने का विकल्प चुना, क्योंकि हम सीरीज बराबर कर सकते थे।' रोहित शर्मा ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले और उनका औसत 40.57 रहा। सबसे लंबे फॉर्म में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का भाग्य 2019 में तब बदला जब उन्होंने ओपनिंग करनी शुरू की। 2020-2024 तक रोहित टेस्ट में भारत के सबसे लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। हालांकि सितंबर 2024 से रोहित का खराब दौर शुरू हो गया और वह रन बनाने में नाकाम रहे।

## व्यापार

## भारत को अपने पाले में रखेगा अमेरिका, ट्रेड डील में खास छूट देकर ट्रंप देने वाले हैं रूस-चीन को मैसेज

एजेंसी नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता होने की संभावना है। इस समझौते से भारत को कुछ खास फायदे मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत को उन भारी टैक्स से बचाया जा सकता है जो 1 अगस्त से दूसरे देशों पर लगने वाले हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी डील पूरी तरह से खास व्यवहार के बारे में है। भारत का एक दल इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वाशिंगटन में है। इसका नेतृत्व राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से भारत को टैरिफ में खास तबज्जो देना सिर्फ आर्थिक नहीं होगा। अलबतता, इसके पीछे एक गहरी सोच भी है। ट्रंप प्रशासन अगर वही करता है जिसके संकेत मिल रहे हैं तो यह रूस और चीन दोनों को साफ संदेश देने का एक तरीका होगा। रूस को यह संकेत दिया जा रहा है कि उसके खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। जो देश उसके साथ व्यापार करते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जबकि भारत जैसे देशों को अमेरिका के साथ खड़े होने पर इनाम मिलेगा। चीन के लिए यह अमेरिका की सप्लाई चेन डायवर्सिफिकेशन और भारत जैसे वैकल्पिक मैनुफैक्चरिंग सेंट्रों को बढ़ावा देने की इच्छा का संकेत है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को



लेकर बातचीत जारी है। इस बातचीत में भारत को कुछ विशेष छूट मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि भारत से आने वाले सामान पर टैक्स कम लगेगा। उदाहरण के लिए अगर वियतनाम से आने वाले सामान पर अमेरिका 20% टैक्स लगाता है तो भारत से आने वाले सामान पर टैक्स कम हो सकता है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका अपने टैक्स नियमों में बदलाव कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग देशों को आने वाले टैक्सों के बारे में बताना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में भारतीय सामान पर 26% टैक्स लगाने की बात कही थी। लेकिन, अभी तक भारत को कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। दूसरी तरफ, दूसरे देशों को भेजे गए पत्रों में अप्रैल में कही गई बातों से कुछ बदलाव हैं। इससे टैक्स को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारतीय

उद्योग जगत के लोगों को उम्मीद है कि 1 अगस्त से पहले एक शुरुआती समझौता हो जाएगा। इससे भारत को भारी टैक्सों से बचने में मदद मिलेगी। यह समझौता भारत के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है। भारत से बाहर जाने वाले सामान का 15% से ज्यादा अमेरिका में जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 86.51 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। इसमें भारत को 40.82 अरब डॉलर का फायदा हुआ था। अगर अमेरिका 26% का टैक्स लगाता है तो भारत को व्यापार में जो फायदा हो रहा है, वह कम हो सकता है। इससे भारत के एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को नुकसान होगा। ऐसे में प्रस्तावित समझौते से भारत को अमेरिका के बाजार में बने रहने में मदद मिल सकती है। आजकल अमेरिका व्यापार को लेकर थोड़ा सख्त हो गया है। इसलिए यह समझौता भारत के लिए एक अच्छा मौका है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'अमेरिकी डील पूरी तरह से खास व्यवहार के बारे में है।' इसका मतलब है कि अमेरिका भारत को दूसरे देशों के मुकाबले कुछ ज्यादा फायदे देगा। ट्रंप को और से भारत को यह 'छूट' देने का कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे भू-जननीतिक निहितार्थों वाला भी लगता है। खासकर रूस और चीन के संदर्भ में।

एजेंसी नई दिल्ली

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं। ये कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हैं। कंपनी का सैमेकित शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 78% बढ़कर 26,994 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 15,138 करोड़ रुपये था। यह प्रभावशाली ग्रोथ विश्लेषकों के अनुमानों को भी पार कर गई है। उन्होंने लगभग 22,069 करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान लगाया था। कंपनी के परिचालन से राजस्व भी मजबूत रहा, जो 5.3% बढ़कर 2,48,660 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,36,217 करोड़ रुपये था। रेन्यूयु ग्रोथ दर्शाती है कि रिलायंस के विविध व्यवसाय, जिसमें तेल-से-रसायन (O2C), खुदरा (Reliance Retail) और दूरसंचार (Jio) शामिल हैं, लगातार विस्तार कर रहे हैं। साथ ही बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। मुनाफे और राजस्व दोनों में यह बढ़ोतरी कंपनी की रणनीतिक पहलों और विभिन्न क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सफलता का प्रमाण है। EBITDA मार्जिन में भी इजाफा



इसके साथ ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 58,024 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 42,748 करोड़ रुपये की तुलना में 36% की शानदार ग्रोथ दर्शाता है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का EBITDA मार्जिन 21.2% तक पहुंच गया, जो पिछले साल 16.6% से 4.6% का महत्वपूर्ण सुधार है। ये आंकड़े कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में परिचालन दक्षता और मजबूत प्रॉफिटैबिलिटी का प्रमाण हैं। इन परिणामों से पहले, रिलायंस के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 0.027% बना रहे हैं। मुनाफे और राजस्व दोनों में यह बंद हुआ। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने इस साल मजबूत रैली दिखाई है। दो साल के अंतराल के बाद भारतीय बाजार के बेंचमार्क से

बेहतर रिटर्न दिया है। इस उछाल ने रिलायंस के बाजार मूल्य में 40 अरब डॉलर का प्रभावशाली योगदान दिया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, रिलायंस शेयरों का वर्तमान प्रदर्शन निफ्टी50 इंडेक्स पर अभूतपूर्व दबदबे को दिखाता है, जो पांच साल की अवधि में सबसे बड़ा अंतर दर्ज कर रहा है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने जनवरी से अब तक 22% मूल्य वृद्धि दर्ज की है, जबकि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स ने करीब 6% की मामूली वृद्धि दिखाई है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने 2025 में 40 अरब डॉलर का बाजार मूल्य अर्जित किया है, जो बेंचमार्क इंडेक्स में कुल मूल्य वृद्धि का लगभग एक तिहाई है। रिलायंस के ये 01 नतीजे निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं और बाजार में कंपनी के प्रति विश्वास को और मजबूत करेंगे। विश्लेषकों की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन और मुनाफे में इतनी बड़ी छलांग यह दर्शाती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बावजूद अपनी विकास गति को बनाए रखने में सक्षम है। यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन न केवल कंपनी के शेयरधारकों के लिए अच्छा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक संकेतक है।

### चीन के दर्द में भारत... अमेरिका के साथ डील में रघुराम राजन की ‘सूझबूझ’ वाली ये चेतावनी कैसी

एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर जारी बातचीत में भारत को 'बहुत सतर्क' और 'सूझबूझ' के साथ काम करने की सलाह दी है। राजन ने कहा है कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को लेकर सतर्क रहना होगा। उनके मुताबिक, विकसित देश कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। भारत की आर्थिक विकास दर अभी छह-सात फीसदी के आसपास है। राजन ने यह भी कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए

गए अतिरिक्त टैरिफ से भारत को कुछ फायदा भी हो सकता है। रघुराम राजन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भारत को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। पीटीआई-बीडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित देश अपने कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। राजन के अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर अभी छह-सात फीसदी के दायरे में है। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के कारण इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते में कृषि जैसे क्षेत्र बहुत जटिल होते हैं। हर देश अपने उत्पादकों को सब्सिडी देता है। भारत के उत्पादक छोटे हैं

और उन्हें कम सब्सिडी मिलती है। अगर कृषि उत्पादों का आयात बिना रोक-टोक के होने लगे तो इससे हमारे किसानों को नुकसान हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वाशिंगटन में बाबाचीत चल रही है। भारत अमेरिका की ओर से लगाए गए 26 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को हटाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा, भारत ने सूटील और एल्युमीनियम पर लगे 50 फीसदी और वाहनो पर 25 फीसदी टैरिफ से भी राहत देने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता इंडोनेशिया के साथ हुए समझौते जैसा ही होगा। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में आयात की अनुमति देना एक बड़ा मुद्दा होगा।

**स्वत्वाधिकारी प्रकाशक दयाराम दिव्य द्वारा मुद्रक वेदांत प्रभाकर, मेधा कम्प्यूटर्स एंड ऑफसेट प्रिंटेर्स, ऑफिस नं. 128, वार्ड नं. 25, नंदभवन कांवाखेड़ा पार्क के पास, भीलवाड़ा 311001 (राज.) से मुद्रित एवं एस-20, प्रतापनगर, भीलवाड़ा (राज.) से प्रकाशित। संपादक दयाराम दिव्य 96949 57624, 87695 58132 \* PRB एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भीलवाड़ा होगा**